भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1516

(जिसका उत्तर सोमवार, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा आवासों की खरीद

1516. श्री कनकमल कटारा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने राजस्थान आवास बोर्ड से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो कितने आवासों की खरीद की गई है और इस खरीद के लिए कितनी निधि व्यय की गई है;

(ग) उक्त में से कितने आवास अभी भी खाली पड़े हुए हैं और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को कुछ आवासों की दयनीय दशा और इन खाली आवासों में असामाजिक गतिविधियों के संबंध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन शिकायतों पर क्या कारवाई की गई है ?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1997 में राजस्थान आवास बोर्ड को 1.02 करोड़ रूपए का भुगतान करके 12 फ्लैट आवासीय प्रयोजनार्थ एवं 02 कमरे कार्यालय के उद्देश्यार्थ खरीदे गए थे।

(ग) 9 फ्लैट और कार्यालय के प्रयोजनार्थ 02 कमरे इनकी दयनीय दशा और रहने योग्य न होने के कारण खाली रहे। इनकी मरम्मत और नवीकरण कार्य (सिविल एवं इलैक्ट्रिक) का प्रस्ताव कार्यालय-अध्यक्ष द्वारा 31.08.2018 एवं 31.10.2018 को अनुमोदित किया जा चुका है। फिलहाल, यह कार्य सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से किया जा रहा है।

(घ) जयपुर में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ड़) ऊपर 'घ' के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

****